बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 125

सोशल मीडिया पर निगरानी

जानकारी के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि उसके नियंत्रण में आने वाले करीब 900 उच्च शिक्षण संस्थान सकारात्मक सोशल मीडिया प्रोफाइल तैयार करें। इससे यह संकेत मिल सकता है कि मंत्रालय की प्राथमिकताएं सही नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रालय का काम एक ऐसे अहम क्षेत्र का प्रबंधन करना है जहां सीमित संसाधनों के साथ ढेरों समस्याएं मुंह बाये खड़ी हैं। बहरहाल, सोशल मीडिया संबंधी पहल में एक परेशान करने वाली बात यह है कि इसकी अनुशंसाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे करीब तीन करोड़ छात्रों से यह कहना भी शामिल है कि वे अपने सोशल मीडिया खातों को अपने संस्थान के खाते से जोड़ें। इससे तमाम छात्र व्यापक निगरानी ढांचे के शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही निजता भंग होने की आशंका भी प्रबल हो जाएगी।

हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों को जारी पत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव ने यह अनुशंसा की है कि प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान अपने कर्मचारियों में से एक को सोशल मीडिया प्रमुख के रूप में नियुक्त करे। यह व्यक्ति फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर संस्थान की प्रोफाइल की देखरेख करेगा। यह व्यक्ति हर सप्ताह संस्थान के बारे में कुछ सकारात्मक खबर भी जारी करेगा और मंत्रालय तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रोफाइल के साथ लिंक करने के बाद रीट्वीट करने, सकारात्मक पोस्ट का प्रसार करने इन संस्थानों की अन्य अच्छी खबरों का प्रसार करने का काम करेगा। इस व्यक्ति की तलाश 31 जुलाई तक की जानी है। यही व्यक्ति छात्रों से यह अनुरोध करेगा कि वे अपने सोशल मीडिया खाते को संस्थान के प्रोफाइल के साथ जोड़ें। छात्रों से भी कहा जाएगा कि वे उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में सकारात्मक खबरों का प्रचार प्रसार करें। द क्विंट द्वारा जानकारी चाहे जाने पर मंत्रालय ने कहा कि छात्रों के खातों को लिंक करने का काम स्वैच्छिक होगा। व्यवहार में देखा जाए तो छात्रों और संस्थानों के बीच का सत्ता समीकरण ऐसा है कि अनुरोध की जगह यकीनन निर्देश ले लेगा।

संभव है कि छात्रों के ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम खातों को बिना उनकी निजी जानकारी हासिल किए भी संस्थान के साथ जोड़ा जा सके लेकिन तब भी मंत्रालय को बहुत बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण करना होगा। इससे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की गोपनीयता समाप्त हो जाएगी क्योंकि उनके खाते उनकी पहचान और संस्थान के नाम के साथ नजर आएंगे।

सरकार की आलोचना करने पर आमतौर पर सरकार समर्थक ट्रोल (सोशल मीडिया पर किसी के पीछे पड़ जाने वाले) हमलावर हो जाते हैं और कुछ मामलों में तो आलोचकों को गिरफ्तार तक किया गया है, ऐसे में यह गंभीर मसला है। अगर सोशल मीडिया की निगरानी शुरू हो गई तो जो छात्र असहमति जताते हैं, उन्हें कई तरह से इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जाहिर है इसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। छात्रों को सकारात्मक पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा लेकिन उन्हें यह भी पता होगा कि मंत्रालय उनकी पोस्ट पढ़ रहा है। इसके अलावा ऐसे लिंक खातों का डेटाबेस चुनावों को प्रभावित करने की मंशा रखने वाले किसी भी संस्थान के लिए सोने की खान हो सकता है। मंत्रालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा अच्छी खबर के प्रसार के अन्य तरीके भी हैं। उदाहरण के लिए मंत्रालय आसानी से सकारात्मक प्रतिपुष्टि और टिप्पणियों की ऑनलाइन व्यवस्था कर सकता है। सोशल मीडिया खाते लिंक करने की राय प्रतिगामी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से अनौपचारिक बातचीत करते हैं, मंत्रालय को इतने बड़े पैमाने पर उसकी निगरानी करके सकारात्मक सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं तैयार करनी चाहिए।

बिनय सिन्हा

बॉन्ड बाजार में दिखते परिपक्वता के संकेत

तनाव से निपटने की परीक्षा से गुजरने के बाद बॉन्ड बाजार अब मजबूती हासिल कर रहा है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **नीलकंठ मिश्रा**

बॉन्ड बाजार को लेकर कितना चिंतित होने की आवश्यकता है? एक ऐसे वित्तीय बाजार में जो क्षमता की कमी से जूझ रहा हो, बॉन्ड बाजार से यही अपेक्षा थी कि वह सरकारी बैंकों की धीमी वृद्धि से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति करेगा। इसके अलावा लंबी अवधि की फंडिंग की आर्थिक आवश्यकता को देखते हुए, इसे वित्तीय ढांचे का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। खासतौर पर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में इसकी जरूरत ज्यादा है जहां, बैंकों के पंचवर्षीय ऋण अपर्याप्त प्रतीत हो रहे हैं। बहरहाल, बीते नौ महीनों में कई डिफॉल्ट हुए। उनमें से कई तो एएए की सर्वोच्च श्रेणी वाले बॉन्डों में हुए। इससे जोखिम लेने की इच्छाशक्ति कम हुई। उच्च ब्याज दर श्रेणी में ऐसा देखने को मिला। इससे यह चिंता उत्पन्न हुई है कि बॉन्ड बाजार अपनी भूमिका निभा पाएगा या नहीं।

परंतु एक सोच यह भी है कि पिछली तिमाहियों में जो दबाव बना वह वास्तव में तेज वृद्धि के दौर के बाद सुदृढ़ीकरण और परिपक्वता की जरूरी अवधि रही होगी। संभावित वृद्धि के मामले में इसे अभी भी लंबी दूरी तय करनी है। परंतु हालिया तनाव बाजार में कुछ अनिवार्य गुणात्मक बदलावों का वाहक है। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले जब मैं एक परिचर्चा में शामिल हो रहा था तो एक बड़े बैंक के कॉर्पोरेट ऋण विभाग के प्रमुख इस बात को लेकर सशंकित थे कि वित्तीय बचत बैंकों के बचाय बॉन्ड म्युचुअल फंड में जाएगी तो क्या होगा? उनकी दलील थी कि तेजी से बढ़ता बॉन्ड बाजार डिफॉल्ट के पहले संकेत पर ठप हो जाएगा। उनकी आशंका थी कि ऐसा कोई भी डिफॉल्ट सामने आने पर ऋणमुक्ति का सिलसिला शुरू हो जाएगा और अपेक्षाकृत नकदीकृत बॉन्ड बाजार उससे निपट नहीं पाएगा। बहरहाल बीते नौ महीनों में कई बड़ी कंपनियां डिफॉल्ट हुई हैं। इनमें दो पर तो एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी थी लेकिन बाजार तो चल रहा है।

बॉन्ड म्युचुअल फंड की प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) में दिसंबर 2017 से गिरावट आने लगी। मौद्रिक नीति समिति के रुख में चौंकाने वाला बदलाव, सरकार द्वारा बॉन्ड जारी करने को लेकर कुछ गलत घोषणाएं और बैंकों के ट्रेजरी विभागों द्वारा बॉन्ड प्रतिफल में तेज इजाफे के बाद खरीदारों की हड़ताल इसकी वजह रही। बॉन्ड म्युचुअल फंड का एयूएम नवंबर 2017 के 8.7 लाख करोड़ रुपये से गिरकर सितंबर 2018 में 7.2 लाख करोड़ रुपये रह गया। दिलचस्प बात है कि बॉन्ड डिफॉल्ट शुरू होने के बाद भी एयूएम में अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं ऋणमुक्ति केवल 300 अरब रुपये रही है। बाजार के लिए यह एक अभूतपूर्व परीक्षा रही। भविष्य के ऋण चक्र के लिए हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए।

बॉन्ड म्युचुअल फंड को भी ऋण आकलन क्षमता सुधारने को कहा गया और क्रेडिट रेटिंग अब अधिक बेहतर हुई हैं। जो फंड निवेश के लिए रेटिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर थे उन्हें अपने बही खाते शिथिल करने पड़े और निवेशक अब म्युचुअल फंड को लेकर अधिक समझ का परिचय दे रहे हैं। बॉन्ड म्युचुअल फंड धारकों और संपदा सलाहकारों को भी डिफॉल्ट का सामना करना पड़ा है इसलिए वे भी बॉन्ड धारिता को कहीं अधिक परखने के बाद काम करते हैं। तय परिपक्वता योजना को एक वक्त तयशुदा जमा का विकल्प माना जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है।

इसके अलावा रेटिंग एजेंसियां जिनकी विश्वसनीयता को काफी झटका लगा, वे अब रेटिंग घटा रही हैं। नियमन में भी सख्ती की जा रही है और एएए श्रेणी की अधिकता को कम किया जा रहा है। इसका असर बॉन्ड प्रतिफल पर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि बॉन्ड बाजार जोखिम को ध्यान में रख रहा है।

फिलहाल जोखिम से बचने की प्रवृत्ति चरम पर है। बॉन्ड बाजार केवल चुनिंदा कंपनियों को फंड दे रहा है जो उसे सुरक्षित लग रहे हैं। कुछ अन्य फर्म को दिया जाने वाला ऋण अधिक जोखिम वाला है तो उसकी दर भी अधिक रखी गई है। जिन कंपनियों पर बाजार को भरोसा नहीं है उन्हें फंड दिया ही नहीं जा रहा है। जोखिम भरे बॉन्ड में कारोबार इतना नकदीकृत है कि उनकी कीमतों पर भी संदेह है। यह एक चक्रीय रुझान है जो हर बाजार में देखने को मिल रहा है। एक बार डिफॉल्ट करने वालों के हटने के बाद हालात बदल जाते हैं।

बीती तीन तिमाहियों की घटनाओं ने भी कर्जदारों के व्यवहार को प्रभावित किया है। पुराने और गड़बड़ी करने वाले कारोबारी समूहों को ऋण पाने की क्षमता बनाए रखने के लिए अपनी परिसंपत्तियों की बिक्री करनी पड़ी है। उन्हें अपनी कंपनियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ऋण की गुणवत्ता पर असर और पूंजी के उचित आवंटन का सकारात्मक प्रभाव अगले चक्र से नजर आने लगेगा।

इस बीच दो चिंताएं उभरी हैं। पहली है वृद्धि पर प्रभाव। बाजार स्वाभाविक रूप से इस उथलपुथल से उबर जाएगा, यह लंबी अवधि की दृष्टि से बेहतर ही होगा। परंतु हो सकता है इसमें काफी वक्त लग जाए। उदाहरण के लिए इन संस्थाओं में से कुछ जिन्हें बॉन्ड बाजार फंड देने से इनकार करता है, वे अब डिफॉल्ट के कगार पर हैं। बहरहाल जब तक वे डिफॉल्ट करेंगी, संभव है कुछ गैर म्युचुअल फंड धारकों को परेशानी महसूस न हो और इसका असर दिखाई न दे। परंतु कई महीनों की यह दिक्कत अनावश्यक प्रतीत होती है। इसी प्रकार रेटिंग में गिरावट, खासतौर पर एएए श्रेणी की रेटिंग में गिरावट के कारण पेंशन और बीमा फंड द्वारा की जाने वाली खरीद में कमी आ सकती है। कई लोगों ने परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की सलाह दी है। अगर ऐसा होता है तो सुधार तेज होगा।

दूसरा, मौजूदा मौद्रिक सख्ती जहां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मौजूदा समस्याओं का कारण है लेकिन वह मौद्रिक चर में गिरावट के कारण भी है। बैंक जब ऋण देते हैं तो वे धन बनाते हैं। अगर व्यवस्था में 100 रुपये हैं और बैंक 5 रुपये ऋण के रूप में देता है तो मूल राशि तत्काल 105 रुपये हो जाती है। वहीं गैर बैंकिंग कंपनियां ऋण देकर पैसे नहीं बनातीं। ऐसे में अगर बाजार में गैर बैंकिंग कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ती है तो मौद्रिक चर स्वयं कम होगा। समस्त मौद्रिक आपूर्ति को स्वस्थ गति से बढ़ते रहने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक को और अधिक आधार राशि तंत्र में डालनी होगी। जबकि बैंक फंडिंग वाले बाजार में ऐसा नहीं होता। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए यह नीतिगत व्यवस्था आवश्यक है।

मीडिया और मनोरंजन के बीच का धुंधला होता फर्क

आंकड़े दिमाग चकरा देने वाले हैं और उनका प्रभाव काफी वास्तविक है। मार्च 2018 में गूगल इंडिया ने 9,337 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था जिसने उसे ज़ी समूह, डिज्नी और टाइम्स समूह के बाद भारत की चौथी बड़ी मीडिया कंपनी बना दिया। गूगल के इस राजस्व का बड़ा हिस्सा सर्च एवं डिस्प्ले विज्ञापनों से आया था। अकेले यूट्यूब से 2,000 करोड़ रुपये गूगल ने कमाए थे जिसके बाद यूट्यूब भारत का सबसे बड़ा ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म या मझोले स्तर का ब्रॉडकास्टर बन गया। गूगल और यूट्यूब 137 अरब डॉलर के आकार वाली दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया फर्म अल्फाबेट के अंग हैं। अल्फाबेट अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर में डिजिटल विज्ञापन बाजार पर दबदबा रखती है। इसके बाद कॉमकास्ट (94.5 अरब डॉलर) का स्थान आता है और फिर 60 अरब डॉलर के राजस्व के साथ डिज्नी मौजूद है।

एक बार फिर भारत का रुख करते हैं। यहां की शीर्ष 15 मीडिया एवं मनोरंजन कंपनियों की सूची पर एक नजर डालते हैं जिनमें गूगल इंडिया भी मौजूद है। इस सूची की दो बातें आपको खासी प्रभावित करेंगी।

पहली, दिग्गज कंपनियों का संयोजन कई तरह की तकनीकों और मीडिया स्वरूपों वाला होता जा रहा है जबकि पहले प्रिंट या टेलीविजन का ही वर्चस्व होता था। ज़ी समूह, डिज्नी, टाइम्स और गूगल के बाद डीटीएच सेवा प्रदाता टाटा स्काई पांचवें स्थान पर है जबकि मल्टीप्लेक्स सिनेमा कंपनी पीवीआर सिनेमाज 11वें स्थान पर है। इस सूची में पीवीआर की मौजूदगी मेरे हिसाब से सबसे प्रशंसनीय बात है क्योंकि लंबे समय से फिल्में हरेक मीडिया संवर्ग का अभिन्न हिस्सा रही हैं लेकिन कभी भी कारोबार के तौर पर उन्हें ऊंचा मुकाम नहीं मिल पाया था। पीवीआर की बढ़त इस बात का पुख्ता संकेत है कि फिल्में भी आखिरकार कारोबार में अहम हो रही हैं, भले ही खुदरा स्तर पर।

दूसरी बात और इस लेख का मुख्य बिंदु यह है कि भारत में मीडिया कारोबार कुछ बड़े बदलाव देखने वाला है। डिज्नी ने पिछले साल फॉक्स को खरीदा

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

आने वाले समय में मीडिया कंपनियों का एकीकरण होने के भी आसार हैं। इस लिहाज से सन टीवी और सोनी अधिक संवेदनशील नजर आती हैं

था जिसके बाद उसे भारत की सबसे बड़ी मीडिया फर्मों में शामिल स्टार का स्वामित्व मिल गया है। ज़ी को जुलाई के अंत तक अपनी 20 फीसदी हिस्सेदारी किसी रणनीतिक या वित्तीय निवेशक के हाथों बेच देनी चाहिए। बहुत लोगों का मानना है कि इस सौदे के जरिये कोई बड़ी वैश्विक कंपनी भारतीय बाजार में आएगी। और फिर तेजी से बढ़ती घरेलू कंपनी रिलायंस जियो भी है जिसका आकार 38,838 करोड़ रुपये का हो चुका है। यह कंपनी अपने आंकड़े साझा नहीं करती है और न ही अपने मीडिया कारोबार के बारे में कोई साक्षात्कार ही देती है। लेकिन जियो वितरण एवं कंटेंट के मोर्चे पर लगातार सक्रिय है। अकेले पिछले साल ही उसने दो केबल वितरण कंपनियों- डेन और हैथवे के अलावा संगीतमय स्ट्रीमिंग ऐप सावन में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदी है। पहले से ही दूरसंचार पर उसका कब्जा है और उसके पास सस्ता डेटा देने की क्षमता भी है। बाकी कंपनियों के उलट जियो का सभी तरह के डेटा संसाधनों और उसके जरिये प्रसारित हो रहे कंटेंट के भी कुछ हिस्से पर नियंत्रण है।

ऐसे में यह तय है कि अगला साल आते-आते 1,67,400 करोड़ रुपये के आकार वाले भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन बाजार पर वर्चस्व के लिए चार दिग्गज कंपनियों- ज़ी, जियो, गूगल और डिज्नी के बीच कड़ा मुकाबला होगा।

ये कंपनियां कहां पर खड़ी हैं? इन सबने डिजिटल कारोबार में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। गूगल और यूट्यूब भले ही राजस्व और ट्रैफिक आंकड़ों के मामले में काफी आगे हैं लेकिन बाकी कंपनियां भी जल्द ही उनकी बराबरी कर सकती हैं। डिज्नी के पास हॉटस्टार और हुलु का स्वामित्व है और इस साल नवंबर में अपना डिज्नी प्लस भी लेकर आने वाली है। जियो असल में डिजिटल जगत की पैदाइशी खिलाड़ी है और उसके पास तमाम ऐप मौजूद हैं। इसके अलावा जियो के पास वूट पेश करने वाली वायकॉम18 में बहुलांश हिस्सेदारी भी है। ज़ी5 भी तगड़े प्रमोशन और मौलिक कार्यक्रमों के बूते दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करने में सफल रहा है।

भारतीय कंपनियों के पास 'विदेशी' की तुलना में नीतिगत मसलों पर खुलकर अपनी बात रखने की क्षमता होने की बात कही जाती रही है लेकिन भारत में 25 साल पुरानी हो चुकी स्टार इंडिया का अब भी विदेशी कहा जाना बहस का मुद्दा हो सकता है। कमोबेश इनमें से सभी कंपनियों के पास सशक्त उत्पाद हैं और किसी न किसी क्षेत्र में उनका बाजार वर्चस्व भी है। डिज्नी के नियंत्रण वाली स्टार इंडिया सामान्य मनोरंजन क्षेत्र में शीर्ष कंपनी है और उसका प्लेटफॉर्म हॉटस्टार भी यूट्यूब के बाद दूसरा बड़ा ओटीटी है। स्टार की ही तरह ज़ी का छोटे एवं बड़े शहरों में दर्शकों पर समान रूप से दबदबा है। इसके पास डीटीएच कंपनी डिश टीवी और केबल प्रसारक सिटीकेबल भी है जबकि स्टार के पास टाटा स्काई में 20 फीसदी हिस्सेदारी है।

हालांकि आने वाले समय में मीडिया कंपनियों का एकीकरण होने के भी आसार हैं। इस लिहाज से सन टीवी और सोनी अधिक संवेदनशील नजर आती हैं। लेकिन भारत में मीडिया नियामक का कोई समुचित ढांचा नहीं होने से कोई भी कंपनी इस हालत में आ सकती है। अमेरिका में संघीय संचार आयोग और ब्रिटेन में ऑफकॉम मीडिया जगत में किसी एक कंपनी के दबदबे पर नजर रखते हैं।

कानाफूसी

गहलोत का किनारा

राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद गांधी परिवार तथा पार्टी के अन्य नेता इस बात पर सहमत हुए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनेंगे। गहलोत को यह संदेश भेजा गया। लेकिन गहलोत ने यह पेशकश ठुकरा दी और कहा कि पार्टी में नई जान फूंकने के लिए आवश्यक है कि किसी नए नेता को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। गहलोत ने राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने का संकेत दिया। बुधवार को राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने के बाद गहलोत ने यह साफ कर दिया कि वह अपने पद पर बने रहना चाहते हैं। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि गत वर्ष विधानसभा चुनावों के दौरान ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को लगता था कि किसी और को नहीं बल्कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए।

बिरला का प्रदर्शन

जिन लोगों को ओम बिरला की क्षमताओं पर संदेह था और जिन्हें लग रहा था कि वह लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाएंगे, वे यह देखकर चकित रह गए होंगे कि दो बार के भाजपा सांसद ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब दे रही थीं। उस वक्त बिरला ने न केवल बाधा उत्पन्न कर रहे विपक्षी सदस्यों को रोका बल्कि उन्होंने सत्ताधारी दल के सदस्यों को भी चेतावनी दी। बिरला ने तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय को सीतारमण के भाषण के अंत में उठकर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं दी जबकि उसी पार्टी के सुदीप बंद्योपाध्याय को रॉय की ओर से सवाल पूछने की इजाजत दे दी। भाजपा के रमेश विधूड़ी जब रॉय को बाधित करने के लिए उठे तो बिरला ने यह कहकर उनको चुप कर दिया कि वह उम्मीद करते हैं कि विधूड़ी जल्दी मंत्री बनेंगे लेकिन फिलहाल वह बाधा उत्पन्न न करें।

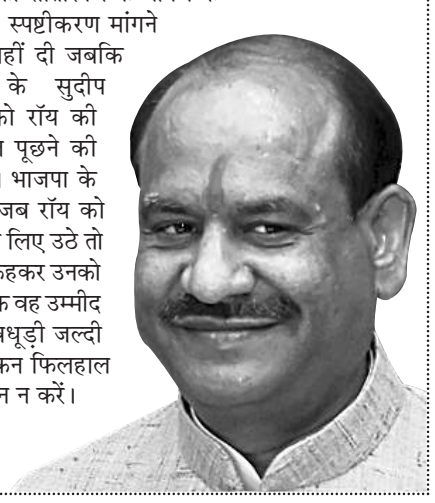

आपका पक्ष

विश्व की बढ़ती जनसंख्या चिंतनीय

प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देश और विश्व में लगातार बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए विश्व जनसंख्या दिवस पर इसकी जागरूकता फैलाने के साथ ही इसके दुष्परिणामों पर भी प्रकाश डाला जाता है। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालन परिषद द्वारा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। दरअसल 11 जुलाई 1987 तक वैश्विक जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब पार हो चुका था। इसे देखते हुए वैश्विक हितों को ध्यान में रखते हुए इस दिवस को मनाने और जारी रखने का निर्णय लिया गया। फरवरी 2019 तक दुनिया की आबादी 7.71 अरब को पार कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र 2019 के वैश्विक जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 136 करोड़ तक पहुंच गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला

आबादी के प्रति जागरूकता के लिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है

देश अभी चीन ही है जिसकी आबादी 142 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। चीन की जनसंख्या सालाना 0.5 फीसदी से बढ़ रही है। इसी दौरान भारत की जनसंख्या 1.2 फीसदी की दर से बढ़ी तथा पाकिस्तान की जनसंख्या 2.4 फीसदी से बढ़ रही है। जनसंख्या दिवस एवं विविध कार्यक्रमों के जरिये जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए विश्व में अनेक कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके बावजूद वैश्विक जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है जिससे विश्व के कई देश अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बढ़ती आबादी की वजह से प्रकृति को प्रमुख रूप से नुकसान हो रहा हैं क्योंकि मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नैसर्गिक संसाधनों का काफी मात्रा में दोहन कर रहा है। कृषि एवं आवास की जरूरत के लिए जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। इस वजह से समूचे विश्व में वन क्षेत्र तेजी से घट रहा है एवं जैव विविधता संकट में है। बढ़ती आबादी की वजह से भारत कई समस्याओं का सामना कर रहा है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, शुद्ध पेयजल की कमी, अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ आदि शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2027 तक चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ देगा। वास्तव में विश्व जनसंख्या दिवस को मनाना तभी सार्थक हो सकता है जब हम बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक रवैया अपनाएं और इसके विभिन्न पहलुओं व हितों पर ध्यान देते हुए जनसंख्या विस्फोट में कमी लाने का प्रयास करें। अन्यथा भविष्य में इसके भयंकर परिणाम देखने मिलेंगे।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

विश्व में शांति की पहल हो

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से मिलने गए। यह एक चौंकाने वाली पहल के साथ साथ आपसी संबंधों को बढ़ाने वाला एक सार्थक कदम है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट यह भी किया कि उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों को एकदम खत्म नहीं किया जाएगा। आगामी बैठक में इस पर विचार होगा और विश्व में और शांति का वातावरण होगा। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पहल करने की जरूरत है जिससे शांति के वातावरण को बल मिले।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।